भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4536
दिनांक 19 मार्च, 2026

अल्पसेवित क्षेत्रों में पेट्रोलियम बुनियादी ढांचे का विस्तार

†4536. **श्री कुंदुरु रघुवीरः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देशभर में विकसित कच्चे तेल की पाइपलाइनों, उत्पाद पाइपलाइनों, एलपीजी बॉटलिंग प्लांटों, भंडारण डिपो और खुदरा ईंधन विक्री केंद्रों सहित पेट्रोलियम बुनियादी ढांचे का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू की गई और वर्तमान में निर्माणाधीन पेट्रोलियम और उत्पाद पाइपलाइनों की कुल लंबाई कितनी है और उनके पूर्ण होने की संभावित समय-सीमा क्या है;

(ग) देश में नई रिफाइनरियों, टर्मिनलों और खुदरा ईंधन विक्री केंद्रों को चिह्नित करने तथा उनके अनुमोदन हेतु सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंडों और दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पिछड़े और अर्ध-शहरी जिलों में बुनियादी ढांचे की कमी का आकलन किया है और भविष्य के विस्तार के लिए ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले पांच वर्षों के दौरान पेट्रोलियम बुनियादी ढांचे के विकास हेतु वर्ष-वार कुल आवंटित और उपयोग किए गए बजट का ब्यौरा क्या है; और

(च) देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में पेट्रोलियम बुनियादी ढांचे का संतुलित और क्षेत्रीय रूप से समान विकास सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ख): पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के परियोजना निगरानी पोर्टल https://pariyojana.mopng.gov.in/ (परियोजना) के अनुसार, तेल और गैस कंपनियों ने विगत 5 वर्षों में 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली 246 परियोजनाएं पूरी की हैं, जिनकी कुल अनुमोदित लागत 2.44 लाख करोड़ रुपये है। पीपीएसी के आंकड़ों के अनुसार, विगत पांच वर्षों के दौरान पूरे देश में विकसित पेट्रोलियम अवसंरचना में, अन्य बातों के साथ-साथ, कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइनों में 5,995 किमी की वृद्धि, 15 नए बॉटलिंग संयंत्र और 10 भंडारण डिपो का जुड़ना तथा 26,451 खुदरा बिक्री केंद्र की वृद्धि शामिल है। इसके अलावा, विगत पांच वर्षों के दौरान पूरे देश में एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र और खुदरा ईंधन बिक्री केंद्र का विकसित पेट्रोलियम अवसंरचना का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा अनुलग्नक 'क' में दिया गया है। विगत 5 वर्षों के दौरान कच्चे तेल की पाइपलाइनों, उत्पाद पाइपलाइनों और पीओएल टर्मिनलों की वर्ष-वार स्थिति निम्नानुसार है:

तिथि	कमीशन की गई कच्चा तेल और उत्पाद पाइपलाइनों का विवरण - लंबाई (किमी)	पीओएल टर्मिनल की संख्या
01-04-2021	28884	303
01-04-2022	29239	309

01-04-2023	32908	310
01-04-2024	34308	313
01-04-2025	34575	314
01-02-2026	34879	313

दिनांक 01.02.2026 की स्थिति के अनुसार देश में कमीशन की गई पेट्रोलियम पाइपलाइनों (कच्चे तेल, पेट्रोलियम और एलपीजी सहित) की कुल लंबाई 34,879 किमी है। कार्यान्वयन के अधीन पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाओं का ब्यौरा अनुलग्नक ख में दिया गया है।

(ग) से (च) भारत में तेल और गैस क्षेत्र को नियंत्रण-मुक्त कर दिया गया है और परियोजनाओं को स्थापित करने का निर्णय संबंधित तेल और गैस कंपनियों के बोर्ड द्वारा लिया जाता है। सरकार की भूमिका केवल एक सूत्रधार की होती है। चूंकि, सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और गैस उपक्रम बोर्ड द्वारा परिचालित और सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध वाणिज्यिक कम्पनियाँ हैं, इसलिए इन सीपीएसई के बोर्ड को परियोजना की प्रकृति और प्रकार, पूंजीगत व्यय (कपेक्स), तकनीकी-आर्थिक और वाणिज्यिक व्यवहार्यता आदि के संबंध में निर्णय लेने की परिचालन स्वायत्तता प्राप्त होती है। संबंधित सीपीएसई का बोर्ड परिचालन दक्षता को अधिकतम करने, परिचालन लागत को कम करने, मांग को पूरा करने, अपनी लाभप्रदता को बनाए रखने के लिए नए स्रोतों की खोज करने और अन्य सामाजिक-आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने हेतु परियोजनाओं के निष्पादन की प्रकृति के संबंध में उचित निर्णय लेता है।

पीएसयू द्वारा नई परियोजनाओं जिनमें रिफाइनरी और खुदरा बिक्री केंद्र शामिल हैं, की पहचान और मंज़ूरी के लिए अपनाए गए सामान्य मानदंड और दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, मांग का विश्लेषण, तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता, भविष्य का दीर्घकालिक दृष्टिकोण और कार्यनीति, भूमि और अन्य संबंधित अवसंरचना की उपलब्धता तथा उत्पाद की स्थिति, रिफाइनरी से निकासी और डाउनस्ट्रीम विपणन अवसंरचना से संबंधित लागत-लाभ पहलू शामिल हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण के लिए तेल डिपो/टर्मिनल खोलना एक निरंतर प्रक्रिया है जो डिपो/टर्मिनल की आर्थिक व्यवहार्यता पर आधारित होती है जिसे उस क्षेत्र की सामान्य आपूर्ति और मांग की स्थिति के साथ-साथ आपूर्ति की लागत में समग्र कमी लाने के उद्देश्य से किए गए अनुकूलन अध्ययन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

विगत 5 वर्षों के दौरान, तेल और गैस सीपीएसई द्वारा आईईबीआर के माध्यम से पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित कुल बजट का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ मे)

क्र.सं	वित्त वर्ष	आवंटित बजट(बीई)	वास्तविक उपयोग
1.	2020-21	98,522	1,11,195
2.	2021-22	1,04,620	1,07,968
3.	2022-23	1,11,354	1,19,027
4.	2023-24	1,06,401	1,36,862
5.	2024-25	1,18,499	1,68,938

सरकार, तेल और गैस कंपनियों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित करके पूरे देश में पेट्रोलियम अवसंरचना का संतुलित और क्षेत्रीय रूप से समान विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें पहुंच, सामर्थ्य, ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये पहलें क्षेत्रीय मांग के पैटर्न पर उचित विचार करने और पूरे देश में पेट्रोलियम उत्पादों की समान उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई हैं।

*****

अनुलग्नक - क

'अल्पसेवित क्षेत्रों में पेट्रोलियम बुनियादी ढांचे का विस्तार' के संबंध में दिनांक 19.03.2026 को श्री कुंदुरु रघुवीर द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4536 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

भारत में पीएसयू एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों की वर्ष-वार/राज्य-वार संख्या और भारत में कमीशन किए गए आरओ की वर्ष-वार संख्या

पीएसयू एलपीजी बॉटलिंग प्लांट (कुल) – संचयी						वर्ष-वार कमीशन किए गए आरओ की संख्या				
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अप्रैल'22	अप्रैल'23	अप्रैल'24	अप्रैल'25	अप्रैल'26	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (अप्रैल - फरवरी)
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
दिल्ली	2	2	2	2	2	0	2	1	1	0
हरियाणा	6	5	5	5	5	248	123	134	259	231
हिमाचल प्रदेश	2	2	2	2	2	75	63	22	90	56
जम्मू एवं कश्मीर	4	3	3	3	3	39	62	32	76	56
लद्दाख	0	1	1	1	1	5	5	3	2	4
पंजाब	8	8	8	8	8	154	92	66	131	119
राजस्थान	11	11	12	12	12	439	388	293	456	381
उत्तर प्रदेश	27	27	28	28	28	871	605	629	1112	788
उत्तराखंड	3	4	4	4	4	79	39	40	75	48
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	26	18	7	77	40
असम	8	8	7	7	7	211	107	47	128	124
मणिपुर	1	1	1	1	1	18	17	11	10	4
मेघालय	0	0	0	0	0	31	16	11	23	37
मिजोरम	0	0	0	0	0	17	24	9	8	10
नागालैंड	1	1	1	1	1	30	18	24	34	19
सिक्किम	1	1	1	1	1	6	2	4	6	2
त्रिपुरा	1	1	1	1	1	14	7	17	20	12
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	1	1	1	3	0	0	1	3
बिहार	8	9	9	9	9	185	203	92	159	187
झारखंड	5	5	5	5	5	104	53	42	176	98
ओडिशा	6	6	6	7	7	181	108	83	233	194
पश्चिम बंगाल	10	10	11	11	12	147	124	68	250	194
छत्तीसगढ	3	4	4	4	4	163	104	65	225	198
दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव	0	0	0	0	0	3	2	0	6	3
गोवा	2	2	2	2	0	5	8	3	8	7
गुजरात	11	11	11	11	2	374	263	207	514	349
मध्य प्रदेश	9	11	11	11	11	593	376	213	497	385
महाराष्ट्र	20	22	22	22	11	627	465	328	475	473
आंध्र प्रदेश	9	9	9	9	10	190	163	135	342	225
कर्नाटक	11	11	11	11	12	436	313	315	618	413
केरल	7	7	7	7	7	164	142	128	162	225
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
पुडुचेरी	1	1	1	1	1	5	8	11	13	6
तमिलनाडु	19	19	19	19	19	410	346	255	483	368
तेलंगाना	5	5	5	5	5	230	217	176	290	188
अखिल भारत	**202**	**208**	**210**	**211**	**214**	**6084**	**4487**	**3473**	**6960**	**5447**

स्रोत: पीपीएसी

अनुलग्नक - ख

'अल्पसेवित क्षेत्रों में पेट्रोलियम बुनियादी ढांचे का विस्तार' के संबंध में दिनांक 19.03.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4536 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्रम. सं.	सीपीएसई	परियोजना का नाम	लक्ष्य पूर्णता तिथि	नवीनतम स्वीकृत लागत (करोड़ रुपये में)
1.	एनआरएल	पारादीप-नुमालीगढ़ क्रूड ऑयल पाइपलाइन [पीएनसीपीएल] और पारादीप में क्रूड ऑयल आयात टर्मिनल [सीओआईटी]	जून/2026	11,407
2.	आईएचबी	कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन	मार्च/2026	10,088
3.	आईओसीएल	नई मुंद्रा पानीपत क्रूड ऑयल पाइपलाइन	जून/2026	9,028
4.	बीपीसीएल	रसायनी, महाराष्ट्र में रिसीप्ट पाइपलाइनों के साथ पीओएल और एलओबीएस प्रतिष्ठान	मई/2026	2,585
5.	एचपीसीएल	विशाख रायपुर पाइपलाइन परियोजना	सितंबर/2027	2,212
6.	बीपीसीएल	इरुगुर से देवांगोंथी तक बहु उत्पाद पाइपलाइन	सितंबर/2026	1,732
7.	बीपीसीएल	पलक्कड़ टीओपी, केरल की स्थापना के साथ-साथ सीसीकेपीएल और आईडीपीएल पाइपलाइन क्षमता का विस्तार	अगस्त/2028	1,130
8.	एचपीसीएल	हल्दिया पानागढ़ पाइपलाइन परियोजना	मई/2026	1,107
9.	ओआईएल	नुमालीगढ़-सिलीगुड़ी उत्पाद पाइपलाइन [एनएसपीएल] की सुविधाओं का उन्नयन	मार्च/2026	860
10.	आईओसीएल	वल्लूर [चेन्नई] में प्रस्तावित जमीनी स्तर के टर्मिनल के लिए कॉमन कॉरिडोर में पीओएल पाइपलाइन बिछाना	मई/2026	829
11.	ओआईएल	पाइपलाइन पुनर्वास परियोजना, चरण- II	दिसंबर/2029	680
12.	आईओसीएल	मौजूदा मुंद्रा-पानीपत पाइपलाइन [पानीपत-चूरवा खंड] की सेवा में कच्चे तेल से उत्पाद में बदलाव	मार्च/2027	359
13.	आईओसीएल	सिलीगुड़ी-झापा पाइपलाइन परियोजना	मार्च/2029	267
14.	बीपीसीएल	बीपीसीएल के मलकापुर पीओएल इंस्टालेशन से हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक एटीएफ पाइपलाइन	सितंबर/2027	215
15.	आईओसीएल	जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक एटीएफ पाइपलाइन	मार्च/2026	165
16.	आईओसीएल	जालंधर से गोइंदवाल साहिब बॉटलिंग प्लांट तक पानीपत जालंधर एलपीजी पाइपलाइन [पीजेपीएल] का विस्तार	मार्च/2027	147
17.	बीपीसीएल	मनमाड-मांगल्या पाइपलाइन खंड का संवर्धन	मार्च/2028	126
18.	एमआरपीएल	जेट्टी 13 से जेट्टी 10/11 तक एरोमैटिक कॉम्प्लेक्स पाइपलाइनों का पुनः रूटिंग	जुलाई/2026	114

स्रोत: परियोजना पोर्टल